भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 242

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुख्य बुनियादी ढांचे का विकास

242. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) के अनुसार, भारत के प्रमुख अवसंरचना उद्योगों की वृद्धि दर मई 2025 में घटकर 0.7% रह गई है, जो पिछले नौ महीनों में सबसे कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर विद्युत जैसे उच्च-भार वाले क्षेत्रों में, मंदी के कारणों को पहचाना है, जो कमजोर मांग की स्थिति और संरचनात्मक अक्षमताओं का संकेत दे रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख क्षेत्रों में विशेषकर मानसून से जुड़ी अस्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर, उत्पादन को स्थिर करने के लिए, क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या यह मंदी 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की विफलता का संकेत देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दस वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की सूची क्या है और उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हासिल की है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): अप्रैल 2025 से मई 2025 तक आठ कोर उद्योगों के समग्र सूचकांक (आईसीआई) में 3.7% की वृद्धि हुई। मई 2025 में समग्र आईसीआई की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 0.7% है। यह मुख्यतः उच्च आधार (मई 2024 के लिए समग्र आईसीआई 168.2 था) के कारण रहा। इसके अलावा, मई 2025 में समग्र आईसीआई 2024-25 के वार्षिक आईसीआई से 2.7% अधिक है। ब्यौरा अनुबंध । में दिया गया है।

सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस के प्रयोग का हिस्सा बढ़ाना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल, संपीडित बायोगैस और बायोडीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करना, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना तथा विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों के लिए देशभर में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन आदि शामिल है। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीडित बायोगैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (सतत) पहल भी शुरू की गई है।

सरकार ने भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत भी की है। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत की गई है। इनमें मोबाइल और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और ड्रोन तथा ड्रोन घटक शामिल हैं। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों ने 1.76 लाख करोड़ रुपए का निवेश सृजित किया है, विनिर्माण आउटपुट को बढ़ाकर 16.5 प्रतिशत किया है तथा 12 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की हैं।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें इस स्कीम के पहले तीन वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान थोक ड्रग्स के निवल आयातक (-1930 करोड़) से अब निवल निर्यातक (2280 करोड़) बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

दिनांक 24.06.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत, 12 क्षेत्रों, नामत: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात, वस्त्र उत्पाद और ऑटोमोबाइल तथा ऑटो घटकों के लिए 21,534 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 28,602 करोड़ रुपए (भूमि की लागत सहित) है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करना, भूखंड स्तर पर तैयार अवसंरचना प्रदान करके नई और विकासशील श्रमशक्ति के लिए जीवनयापन और सामाजिक सुविधाओं की स्थिति को को बेहतर करना तथा उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और सुदृढ़

अवसंरचना उपलब्ध कराकर देश में विनिर्माण निवेश की दिशा में सहायता प्रदान करना है।

इसके अलावा, सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करने हेतु 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। अब तक, डीपीआईआईटी द्वारा 1.75 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमें, नामत: स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) कार्यान्वित कर रही है।

सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग नामक प्रमुख कार्यक्रम के तहत भी अनेक पहलें शुरू की हैं जिनमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बिजनेस-रेडी आकलन, जन विश्वास और व्यवसायों व नागरिकों के अनुपालन बोझ को कम करना शामिल हैं। सरकार विनियमन की लागत नामक कार्य भी कर रही है, जिसका उद्देश्य सेवाओं की प्रशासनिक लागत के संबंध में समस्यापूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना तथा सुधार करना है।

अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मानीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए कार्यक्रम, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय करना, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, माल एवं सेवा कर लागू करना, कॉर्पोरेट कर की दर में कमी, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय आदि प्रमुख हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 242 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आठ प्रमुख उद्योगों के समग्र सूचकांक (आईसीआई) तथा बिजली और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्र के लिए आईसीआई का रुझान

माह/वर्ष	**समग्र सूचकांक (आधार 2011-12)**	**बिजली का सूचकांक**	**पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का सूचकांक**
भार (%)	**100.00**	**19.85**	**28.04**
अप्रैल-24	161.7	212.0	137.9
मई-24	168.2	229.3	141.8
जून-24	163.7	222.8	134.1
जुलाई-24	162.8	220.2	143.3
अगस्त-24	156.3	212.3	134.0
सितम्बर-24	155.4	206.9	134.1
अक्तूबर-24	162.4	207.8	135.5
नवंबर-24	159.1	184.1	138.4
दिसंबर-24	169.4	192.8	149.1
जनवरी-25	173.8	201.7	147.2
फ़रवरी-25	163.0	194.0	133.5
मार्च-25	182.9	219.5	147.3
2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025)	**164.9**	**208.6**	**139.7**
अप्रैल-25	163.3	215.7	131.7
मई-25	169.4	216.0	143.3
अप्रैल 2025 की तुलना में मई 2025 में वृद्धि (%)	**3.7**	**0.1**	**8.8**
मई 2024 की तुलना में मई 2025 में वृद्धि (%)	**0.7**	**-5.8**	**1.1**
2024-25 की तुलना में मई 2025 में वृद्धि (%)	**2.7**	**3.5**	**2.5**

*****